**बेरोजगार हरिजन**

3151. **श्री राम सागर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे विभिन्न रोजगार कार्यालयो मे वर्ष बेरोजगार हरिजनो की अद्यतन सख्या क्या है , और

(ख) क्या सरकार उनके लिए कोई राहत शिविर स्थापित करेगी क्योकि ऐसी कोई सम्भावना नही है कि उन्हें कभी रोजगार मिलेगा ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयो के चालू रजिस्टर मे रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की सख्या से सम्बन्धित है । (यह जरूरी नही है कि वे सभी बेरोजगार हो), जो कि 30 जून, 1977 को 12 08 लाख थी ।

(ख) राहत शिविर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नही है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को आरक्षित तथा गैर आरक्षित दोनो प्रकार की रिक्तियो के लिए भेजा जाता है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को रोजगार के लिए और अच्छी तरह तैयार करने के लिए अध्यापन व मार्गदर्शन की योजना भी है ।

**Entrusting Administration and Enforcement of the Bidi Workers Welfare Cess Act and Bidi Workers Welfare Fund Act**

3152 DR VASANT KUMAR PANDIT Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state

(a) whether the Administration of the Bidi Workers Cess Act and the Bidi Workers Welfare Fund Act has been entrusted to the Central Government;

(b) the basis for this arrangement since the responsibility for maintenance of industrial relations in the bidi industry is entrusted to the State Governments;

(c) whether the industries for which labour welfare funds have so far been constituted, fall within the Central sphere, while the bidi Industry falls in the State sphere; and

(d) whether the Central Government are considering the question of entrusting the administration and enforcement of the above two legislations to the State Governments?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) Yes Sir

(b) The Acts as passed by the Parliament require the Central Government to administer them As such the Bidi Workers Welfare Fund is also being administered by the Central Government

(c) Coal Iron Ore Limestone and Dolomite and Mica Mines for which welfare funds have been created come under the jurisdiction of the Central Government for the purpose of the Industrial Disputes Act The Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act 1966 is administered by the State Governments

(d) One of the State Governments has suggested that the cess collected by the Central Government for the welfare of Bidi Workers should be transferred to the State Governments for administering welfare activities This suggestion is being examined

**डाक-तार विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों (पोस्टमैन आदि) के वेतन में वृद्धि**

3153. **श्री रामजी लाल सुमन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों (पोस्टमैन आदि) के वेतन मे वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और